

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुरपीठासीन अधिकारी :- अनीता मीना, आर.ए.एस.प्रकरण संख्या 5/2018 (बांसवाड़ा आर्डर)

राजेन्द्र कुमार पिता नाथूलाल जी शाह, जाति नैमा महाजन, निवासी बांसवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्त

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. अधीक्षक, जनजाति बालक छात्रावास, घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 ख रा.भू-राजस्व अ. 1956 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घाटोल दिनांक 21.12.2010 क्रमांक/एफ()राजस्व अभियान/2010/1427-428

---/---

उपस्थित (वक्त बहस): 1- श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्त
2- श्री ललित पाटीदार अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट

---::---

निर्णयदिनांक 12-10-2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी घाटोल ने अपने आदेश क्रमांक/एफ()राजस्व अभियान/2010/1427-428 दिनांक 21-12-2010 ग्राम घाटोल की आराजी नंबर 5824 रकबा 0.14 हैक्टर भूमि जनजाति बालक छात्रावास घाटोल हेतु आवंटित की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त राजेन्द्र कुमार द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28-09-2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री ललित पाटीदार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्त ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 11-08-2018 को मौके पर कुछ व्यक्ति आये एवं प्रार्थी के निर्माण कार्य को रूकवाने लगे तब प्रार्थी/अपीलान्त को उक्त आवंटन की जानकारी हुई। तत्पश्चात् नकले प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विपक्षी/रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपील करीब 8 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है



एवं इसके लिए कोई पर्याप्त कारण प्रार्थी ने नहीं बताया है। अतः अपील बेरुन मयाद होने से इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलान्ट द्वारा 21-12-2010 की अपील दिनांक 28-09-2018 को प्रस्तुत की है, जबकि अपील 60 दिवस में अर्थात् दिनांक 20-02-2011 तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन अपीलान्ट द्वारा यह अपील करीब 7½ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो आधार अपीलान्ट ने अपने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित किये वह न तो उचित प्रतीत होता है, न ही इतनी लम्बी देरी का कोई पर्याप्त कारण है। तदनुसार अपील बेरुन मयाद होने से मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरुन मयाद होने एवं अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार साबित नहीं होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश दिनांक 21-12-2010 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12-10-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर